

रोजगार मेले में एक बार फिर युवा शक्ति से विकसित भारत के संकल्प को जोड़ा

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ माह के अंतराल के बाद आयोजित रोजगार मेले में एक बार फिर युवा शक्ति से विकसित भारत के संकल्प को जोड़ा। साथ ही यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया कि युवाओं की शिक्षा से लेकर रोजगार और उद्यमिता के लिए सरकार सतत काम कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार हर माचें पर काम कर रही है।

शनिवार को आयोजित यह 20वां रोजगार मेला था, जिसमें 51 हजार से

अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। सरकारी आंकड़े के मुताबिक, प्रधानमंत्री की इस पहल के तहत दिए गए रोजगार का कुल आंकड़ा अब 12.75 लाख पर पहुंच चुका है। रोजगार मेले का यह क्रम पीएम द्वारा 2022 में दस लाख कुल नौकरियों के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।

आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं, जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। ये लक्ष्य है- 2047 तक विकसित भारत बनाने का। इसमें आप जैसे युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। युवा होने के नाते विशेष तौर पर अन्य युवाओं के प्रति आपकी विशेष जिम्मेदारी है। युवाओं के टैलेंट और स्किल्स ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है।

दुनिया को हमारी युवा शक्ति से बहुत उम्मीदें हैं। हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन से हर वर्ग को लाभ का दावा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये एफटीए युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं।

बीते वर्षों में भारत सरकार का निरंतर जोर युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के प्रयास। हमारी कोशिश है कि युवाओं की पढ़ाई और उनका कौशल बदलती इकोनॉमी की जरूरतों के साथ चलें।

चीनी भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आगामी त्योहारी सीजन और चीनी की बढ़ती मांग को देखते हुए थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, 10 टन से अधिक मासिक खपत वाले औद्योगिक उपभोक्ता अब 30 दिनों की जरूरत के बराबर चीनी रख सकेंगे। पहले 15 दिनों से अधिक का अतिरिक्त भंडार केवल टैरिफ रेट कोटा या एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत आयातित चीनी से ही रखा जा सकेगा। खुले बाजार से खरीदी गई चीनी के लिए 15 दिनों की खपत की सीमा बरकरार।

सरकार ने टीआरक्यू के तहत 10 लाख टन चीनी आयात की अनुमति दी है। साथ ही एएस के तहत निर्यात के लिए खरीदी गई चीनी की घरेलू बिक्री की अनुमति भी दी गई है। भंडार पर निगरानी के लिए थोक उपभोक्ताओं को प्रत्येक शुक्रवार ऑनलाइन

केशरी दर्पण समाचार पत्र के पत्रकार बने

भारत के किसी भी जनपद, तहसील या थाना क्षेत्र में केशरी दर्पण समाचार पत्र के पत्रकार बनने के लिए संपर्क करें। आप केशरी दर्पण समाचार पत्र की वेबसाइट से भी के माध्यम से भी पत्रकार बन सकते हैं। समाचार पत्र की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें लॉगिन करें आप स्वयं केसरी दर्पण समाचार पत्र की वेबसाइट पर समाचार फोटो आदि भी अपलोड कर सकते हैं। सोनीपत जनपद में श्रीमती अंजू देवी पति श्री कृष्ण पाल, सोनीपत मो. 9416957607

निवेदक-सुभाष चंद, संपादक, केशरी दर्पण (हिंदी साप्ताहिक) 9837749557

www.kesharidarpan.com

पोर्टल पर अपने चीनी स्टॉक की जानकारी देनी होगी। सरकार ने कहा कि यह फैसला औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ चर्चा के बाद लिया गया है। इस बीच, सरकार ने बताया कि मिल स्तर पर चीनी की कीमतें करीब 25 प्रतिशत घटी हैं, लेकिन खुदरा कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत ही कमी आई है। अगस्त में 65 रुपये प्रति

किलोग्राम के उच्च स्तर से खुदरा कीमत अब करीब 58.50 रुपये है। सरकार ने व्यापारियों से कम कीमतों का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील की है। एक अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले नए चीनी सत्र में गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़कर 365 रुपये प्रति क्विंटल होगा।

छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मंच साझा किया

रिंकू/एजेंसी, नई दिल्ली। ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव किया। हाल ही में इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की थी। पार्टी ने कहा कि राजनीति में मजाक-मस्ती के लिए जगह होनी चाहिए। लोकसभा सांसद सौगत रॉय ने कहा कि राहुल गांधी ने बस वही दोहराया जो खुद पीएम मोदी ने कहा था।

इसमें कोई अपमान नहीं किया गया है। समाचार एजेंसी से बात करते हुए सौगत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था, उसे बस दोहराया गया है, यह किसी का

अपमान नहीं है। राजनीति में मस्ती-मजाक के लिए जगह होनी चाहिए। उनका यह बयान कांग्रेस और ममता की टीएमसी के बीच नई नजदीकियों के संकेतों के बीच आया है।

शनिवार को राहुल गांधी ने अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान इंदौर में स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि के साथ मंच साझा किया। कार्यक्रम में नेता विपक्ष की टिप्पणियों और मिमिक्री वाले हाव-भाव की बीजेपी नेताओं ने आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी दिवंगत मां का मजाक उड़ाया गया।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता

बनर्जी, जो इस गुट की प्रमुख हैं, ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगी। नंदीग्राम सीट सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई थी। अधिकारी ने ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर सीट को अपने पास रखा था, जहां उन्होंने अप्रैल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता को हराया था। ममता बनर्जी की घोषणा के कुछ ही समय बाद, कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार मिलन प्रधान को 2007 के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधान को 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति बंद नहीं

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए एक अक्टूबर से आधार बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करना जरूरी होगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी का लाभ केवल पात्र उपभोक्ताओं को मिले और फर्जी या डुप्लीकेट कनेक्शन के जरिए इसका दुरुपयोग न हो। जिन ग्राहकों ने पहले ही आधार बायोमीट्रिक सत्यापन या ई-केवाईसी करा लिया है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी ग्राहकों यानी करीब 89.9 प्रतिशत उपभोक्ताओं का आधार बायोमीट्रिक सत्यापन पूरा हो चुका

था। सितंबर 2026 में 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर करीब 210 रुपये की अप्रत्यक्ष सब्सिडी मिल रही है। मंत्रालय के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं ने अब तक सत्यापन नहीं कराया है, वे इसे पूरा करने के बाद सब्सिडी वाले सिलिंडर की बुकिंग कर सकेंगे।

उपभोक्ता एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर या सिलिंडर की डिलीवरी के समय डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल एप के जरिये आधार बायोमीट्रिक सत्यापन करा सकते हैं। आधार बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति बंद नहीं होगी, लेकिन उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ग्राहकों को सिलिंडर बाजार मूल्य पर लेना होगा।

व्यापारी यूपीआई से भुगतान लेने में आनाकानी करने लगे

राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इसका कोई असर नहीं

तरुण/एजेंसी, नई दिल्ली। दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 15 अक्टूबर से मचेंट डिस्काउंट रेट लागू होना है, लेकिन अभी से इसका विरोध होने लगा है। गाजियाबाद में व्यापारी यूपीआई से भुगतान लेने में आनाकानी करने लगे हैं तो झांसी में कुछ पेट्रोल पंपों ने यूपीआई से पेमेंट नहीं लेने की सूचना चस्पा कर दी है। हरियाणा के कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर रात के समय स्कैनर व्यवस्था काफी कम कर दी गई है। मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने 23 सितंबर को नो-यूपीआई दिवस मनाने का निर्णय लिया है। उस दिन वे यूपीआई से भुगतान नहीं लेंगे।

राजधानी दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में इसका कोई असर नहीं है, लेकिन, मध्य प्रदेश के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर विरोध दिखने लगा है। मध्य प्रदेश के 125 व्यापारी संगठनों ने शनिवार को इंदौर में बैठक कर 23 सितंबर को नो-यूपीआई दिवस मनाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि पेट्रोल पंप 16 अक्टूबर से दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि हमने अपने राज्य स्तरीय समन्वयक को भी पत्र लिखा है। झांसी में कुछ पेट्रोल पंपों पर यूपीआई के जरिये 2 हजार से अधिक का

पेट्रोल-डीजल नहीं देने का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। हालांकि झांसी पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव बब्बर का कहना है कि संगठन स्तर पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पंप पर लगी सूचनाएं संचालकों का व्यक्तिगत फैसला हो सकती हैं।

गाजियाबाद में कुछ दुकानदारों ने ग्राहकों से नकदी की मांग करनी शुरू कर दी है। एक कन्फेक्शनरी शॉप के बाहर नोटिस लगाया गया है कि यूपीआई से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ हेयर सैलून के बाहर भी यूपीआई के बजाय नकद में भुगतान करने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। गाजियाबाद पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री बृजमोहन सिंघल का कहना है कि पहले क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर भी फ्लैट पांच रुपये पंप संचालक के खाते से कटते थे, जो सरकार वापस भेजती थी। एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पेट्रोलियम पदार्थ में इतना मार्जिन नहीं है, इसलिए पेट्रोल पंप संचालकों का नुकसान होगा। इसके चलते क्रेडिट कार्ड जैसी पांच रुपये वापस खाते में आने की व्यवस्था ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी की जाए।

हिसार में ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि एसोसिएशन ने वित्तमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री को पत्र भेजकर पेट्रोल पंपों को एमडीआर से पूरी छूट देने की मांग की है। पटना समेत कई जगह की एसोसिएशन ने भी वित्त मंत्री को पत्र लिखकर राहत की मांग उठाई है।

10 वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किसान क्रेडिट कार्ड योजना का

प्रमोद कश्यप/एजेंसी, लखनऊ। रविवार रात प्रदेश सरकार ने 10 वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। इसमें कई अधिकारियों से महत्वपूर्ण विभाग लेकर दूसरे अधिकारियों को सौंपे गए हैं। कुछ अधिकारियों को वर्तमान पद के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फेरबदल में उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद, ऊर्जा और श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।

अमित कुमार घोष को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा बनाया गया है। अभी उनके पास चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार था।

अमृत अभिजात को वर्तमान पद के साथ परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वी. हेकाली झिमोमी को प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के स्थान पर प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।

महेंद्र प्रसाद अग्रवाल को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से हटाकर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। अनिल कुमार को प्रमुख सचिव पंचायतीराज से हटाकर प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले आयुक्त, खाद्य एवं रसद की

सपा अध्यक्ष भाजपा को घेरने में जुटे

प्रमोद कश्यप/एजेंसी, लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा को घेरने में जुटे। अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो रिमोट सेंसिंग तकनीक से जांच कराएंगे कि गाड़ी कैसे पलटी।

रास्ते में आने के बीच कहां-कहां क्या बदला। फेक एनकाउंटर्स की भी जांच कराकर आवश्यक कारवाई की जाएगी। इसके लिए जितना भी धन लगेगा, सरकार व्यवस्था करेगी। एप्लीकेशनों और आधुनिक तकनीकों का सबसे ज्यादा प्रयोग खेतीबाड़ी, इलाज और पढ़ाई में जिम्मेदारी दी गई है। पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के मुद्दे पर पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से इनकी अनबन चल रही थी। मंत्री ने इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इनकी शिकायत मुख्यमंत्री से की थी।

डॉ. एमकेएस सुंदरम को कृषि विभाग से जुड़े कई अहम दायित्व सौंपे गए हैं। उन्हें प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि विभाग में इन दायित्वों को संभाल रहे रविंद्र को प्रमुख सचिव पंचायती राज बनाया गया है।

अमित गुप्ता को वर्तमान पद के साथ

किया जाएगा।

रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश ने कहा कि मिशन-2027 को देखते हुए हर विधान सभा में 27 हजार वोट बढ़ाए जाएंगे या यूं कहें कि भाजपा के इतने ही वोट कम किए जाएंगे।

आरोप लगाया कि प्रदेश में 72 जिलों में 151 से ज्यादा स्थानों पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी गईं, जिसमें बलिया में सर्वाधिक घटनाएं हुईं। भाजपा सरकार में एक्सप्रेसवे के नाम पर जेबें भरी गईं।

प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऊर्जा विभाग में भी बड़ा बदलाव किया गया है। रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और यूपीएसएलडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है।

डॉ. आशीष कुमार गोयल, जो ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष पद संभाल रहे थे, उन्हें अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन बनाया गया है।

लाभ लाखों किसानों ने उठाया

प्रमोद कश्यप/एजेंसी, लखनऊ। किसानों के बहुउपयोगी योजना के रूप में उभर कर सामने आई किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्रदेश के लाखों किसानों ने उठाया, लेकिन केसीसी का लाभ लेने वालों में डिफाल्टर्स की संख्या बढ़ गई, जो बैंक और शासन दोनों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। ऐसे में योगी सरकार ने इसके समाधान और किसानों को सुविधा के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिल सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की ओर से किसानों को कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। सरकार का मानना है रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होने से किसान ऋणमाफी की मानसिकता से बाहर निकलेंगे और दीर्घकालीन पूंजी निवेश कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित होंगे।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण सिर्फ छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाएगा। राज्य सरकार ऋणों पर पांच प्रतिशत अनुदान देगी। यह

अनुदान उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो निर्धारित अवधि के अंदर किस्तें अदा कर रहे हैं।

नाबार्ड उच्च ब्याज दर पर ऋण देता है, जिसका भुगतान कई बार किसान नहीं कर पाते थे। ऐसे में प्रस्तावित योजना के अंतर्गत लघु किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत रियायती वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाएगा। योगी सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। यह योजना लॉन्च की गई। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है और साथ ही उसके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का का दस्तावेज हों।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना' उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से चलाई जाएगी। बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालिक ऋण न्यूनतम ब्याज पर दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ब्याज पर अनुदान देगी, जिससे खेती किसानों के लिए लिया जाने वाला यह ऋण काफी सस्ता पड़ेगा। ऋण पांच साल और उससे अधिक अवधि के लिए दिया जाएगा।

कोशिश करो

तैयार रहो

सेवा करो

श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन

पंजीकरण संख्या- S/703/2014-दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2014, संपूर्ण भारतवर्ष
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्काउट्स-गाइड्स जर्मनी से भी संबंध
प्रधान कार्यालय: निर्भय एनक्लेव, खेकड़ा (बागपत) उ.प्र. पिन-250101
Email:- subhashchand4@gmail.com, Mob- 09837749557- 7906984078



संपूर्ण भारतवर्ष में श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, स्काउट-गाइड प्रशिक्षण कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सिलाई सेंटर हेतु संपर्क करें।
स्काउट गाइड संस्थाओं NCC, NSS से जुड़े भाई-बहनो जुड़ने को प्राथमिकता।
(सुभाष चंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव, श्रीराम बाजपेयी स्काउट गाइड एसोसिएशन)

राहुल गांधी ने सत्यानिकेतन पीजी इमारत हादसे में जवाबदेही पर सवाल खड़े किए

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली के सत्यानिकेतन में पीजी इमारत गिरने से सात छात्रों की मौत के बाद छात्रावास और निजी पीजी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हादसे को लेकर व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं।

रविवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने मृतक छात्र अर्पित झाड़ के परिवार का जिक्र किया और पूछा कि आखिर उस मासूम की क्या गलती थी। उन्होंने कहा कि अर्पित का परिवार पर्याप्त और सुरक्षित छात्रावास उपलब्ध नहीं होने के कारण अपने बेटे को असुरक्षित जगह पर रहने के लिए छोड़ने को मजबूर था।

राहुल गांधी ने सवाल किया कि यदि सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन

किया गया होता तो क्या इस हादसे को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने सपनों से भरी कई जिंदगियां छीन लीं और उम्मीदों से जुड़े परिवारों को तबाह कर दिया। सत्य निकेतन की त्रासदी में अपने बेटे, अर्पित जाज, को खोने वाला परिवार डबडबाई आंखों से यही सवाल पूछ रहा है। अगर अच्छे और सुरक्षित हॉस्टल होते, तो उन्हें अपने बच्चे को ऐसी खतरनाक जगह में रखने के लिए मजबूर न होना पड़ता।

उन्होंने छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग करते हुए कहा कि अर्पित का परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा देश जवाबदेही चाहता है। उनका सवाल था कि नए और सुरक्षित छात्रावास क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं और छात्रों को असुरक्षित पीजी में रहने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है।

राहुल गांधी ने सत्यानिकेतन हादसे की जांच की प्रगति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि इस मामले में जांच अब तक कहां तक पहुंची है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैम्पस के पास सत्यानिकेतन में 6 सितंबर को एक इमारत ढह गई थी। इसमें लड़कों के लिए पीजी आवास संचालित हो रहा था। हादसे में सात छात्रों की मौत हुई थी। घटना के बाद पुराने आवासीय भवनों में चल रहे निजी पीजी और छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने पीजी और निजी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा तथा ऐसे प्रतिष्ठानों के नियमन से जुड़े प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय एमसीडी जांच के आदेश दिए थे।

एनएच-44 पर 22 से 25 सितंबर तक मुख्य मार्ग पर यातायात आवागमन प्रभावित रहेगा निर्माण कार्य के दौरान संभावित यातायात असुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना निर्धारित समय के अनुसार बनाएं तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सोनीपत पुलिस का सहयोग करें।

अंजू देवी, सोनीपत। एनएच-44 पर कुंडली बार्डर के पास फुट ओवरब्रिज-1 के एक्शन कार्य के चलते पुलिस की ओर से यातायात की सुचारू एवं सुरक्षित आवाजाही के लिए रात्रिकालीन डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक लगभग 400 मीटर तक मुख्य मार्ग पर यातायात आवागमन प्रभावित रहेगा। यातायात को आवश्यकता के

अनुसार निर्धारित सर्विस रोड से डायवर्ट किया जाएगा।

डायवर्जन अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती एवं आवश्यक यातायात प्रबंध किए जाएंगे। मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील है कि निर्धारित डायवर्जन प्लान का पालन करें तथा मौके पर यातायात पुलिस द्वारा दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करें निर्धारित मार्गों का ही प्रयोग करें।

आमजन से अनुरोध है कि निर्माण कार्य के दौरान संभावित यातायात असुविधा को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना निर्धारित समय के अनुसार बनाएं तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सोनीपत पुलिस का सहयोग करें।

भाजपा ने गरीबों को हमेशा धोखा दिया, गरीबों के आरक्षण में दबंगों को शामिल कर गरीबों का पिछले 26 वर्षों से मार दिया, आओ बागपत लोकसभा को भाजपा मुक्त करे

बागपत लोकसभा की जनता जनार्दन आशीर्वाद दे तो एक बार फिर 2029 में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा



निवेदक-

सुभाष चंद कश्यप

पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा
2014 निर्दलीय, 7906984078

पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर
11 जनपद बागपत-2015

राष्ट्रीय महासचिव श्रीराम बाजपेई स्काउट
गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया

पता- कस्बा खेकड़ा जनपद बागपत उत्तर
प्रदेश -250101

सम्पादकीय.....

केंद्र के दम पर विकसित भारत नहीं किया जा सकता ?

केंद्रीय वित्त मंत्री व राज्यों के वित्त मंत्रियों के बीच बैठक में कि अकेले केंद्र के दम पर विकसित भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता है। बैठक में आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने राज्यों से खुलकर कहा कि भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए केंद्र के बजट से काम नहीं चलेगा। मतलब राज्यों को भी अपने बजट को खासकर गुणवत्ता वाले खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाना होगा। इस काम लिए राज्यों को अपने राजस्व को भी बढ़ाना होगा। राज्यों के वित्त मंत्रियों से कहा गया कि सवाल इस बात का नहीं है कि उनके पास कितनी वित्तीय व्यवस्था है, सवाल इस बात का है कि कोई राज्य आसानी से कितना अधिक निवेश ला सकता है।

इस काम के लिए राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर व मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने, निजी निवेश के प्रोत्साहन को लेकर माहौल बनाने और हाउसिंग सेक्टर के लिए आसान वित्तीय व्यवस्था पर फोकस करने के लिए कहा गया। ये सभी कारक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अभी हाउसिंग फाइनेंस की दर राज्यों के जीडीपी का 2.5 प्रतिशत है। राज्यों से इसे अगले पांच साल में बढ़ाकर तीन प्रतिशत तक लाने के लिए कहा गया है।

हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां सभी राज्यों को आसानी से निवेशक मिल सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस हाउसहोल्ड निवेश, निर्माण कार्य व शहरीकरण से जुड़ा है। इस सेक्टर में राज्य निवेश की सुविधा देकर विकास के लिए वित्त का दायरा बढ़ा सकते हैं। मैन्यूफैक्चरिंग के प्रोत्साहन के लिए सभी राज्यों से औद्योगिक बिजली की दर, माल ढोने व जमीन की लागत और वित्तीय व्यवस्था की लागत को कम करने के लिए कहा गया।

वित्त मंत्रियों की बैठक में यह बात सामने आई है कि भारत में जमीन और वित्तीय व्यवस्था की लागत मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों से अधिक है। राज्यों को अपने-अपने यहां मैन्यूफैक्चरिंग की कुल लागत को दुनिया के अन्य देशों से कम करने की कोशिश करनी होगी।

राज्यों से कहा गया कि वे जमीन, बिजली, सड़क कनेक्टिविटी, कारोबारी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान और औद्योगिक रिश्तों को बेहतर बनाने का काम करें। दूसरी तरफ निजी निवेशकों को रिन्युएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डाटा सेंटर, टूरिज्म, कृषि संबंधी वैल्यू चेन व सर्कुलर इकोनामी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें।

राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मोदी पर कॉमेडी, बीजेपी नेताओं ने कड़ी आलोचना की

रिंकू/एजेंसी, नई दिल्ली। इंदौर में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कॉमेडी को लेकर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। राहुल गांधी ने स्टैंड-अप कॉमेडियन पुलकित मणि के साथ मंच पर कुछ बातें कहीं और इशारे किए, जिनसे साफ पता चलता था कि वे मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से शेयर किए गए वीडियो में कॉमेडियन पुलकित को विदेशी नेताओं के साथ बातचीत करने के पीएम मोदी के अंदाज की नकल करते हुए देखा जा सकता है।

उनके इस एक्ट में प्रधानमंत्री की विदेश नीतियों और एक रैली की उस घटना का भी जिक्र था, जिसमें पीएम मोदी ने अपना भाषण रोककर भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग महिला के लिए कुर्सी मंगवाई थी। पुलकित के उस घटना का जिक्र करने पर राहुल गांधी को हंसते हुए देखा गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने आज सुबह एक वीडियो बयान में कहा कि राहुल गांधी ने एक मां का मजाक उड़ाकर महिलाओं का अपमान किया है। केशवन ने कहा कि कोई भी सभ्य और

सही सोच वाला व्यक्ति ऐसी अभद्र और घटिया हरकतों को मजेदार नहीं मानेगा लेकिन राहुल गांधी को उस मंच पर जोर-जोर से हंसते हुए देखा गया जिसे वे उनके साथ साझा कर रहे थे। राहुल गांधी द्वारा ऐसी असभ्य संस्कृति को बढ़ावा देने की वजह से ही वे और कांग्रेस युवाओं से जुड़ने में नाकाम रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने नेता शशि थरूर ने भी इस मोर्चे पर पार्टी की नाकामी को माना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कड़वी नफरत वाली राजनीति ही वह वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी और उसके छात्र संगठन एनएसयूआई को दिल्ली यूनिवर्सिटी से खदेड़ दिया गया। एक तरफ मोदी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कुर्सी का इंतजाम करके संवेदनशीलता दिखाई, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को कल तब मजा करते हुए देखा गया जब ऐसे ही बुजुर्गों का बेशर्मी से अपमान किया जा रहा था। राहुल गांधी, जो मसखरों और ऐसे भद्दे सर्कस शो का समर्थन करते हैं, उन्हें एक राजनीतिक नेता के तौर पर गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।

बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट शुल्क को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब ने समिति की रिपोर्ट का पुरजोर बचाव किया है। विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ रिकॉर्ड पर है और यह रिपोर्ट पूरी तरह से सर्वसम्मति से और तय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपनाई गई थी।

महताब की यह टिप्पणी तब आई जब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में उन दावों को खारिज कर दिया कि विपक्षी सदस्यों ने डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर लागू करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महताब ने कहा कि समिति रिपोर्ट पर चर्चा, तैयारी और उसे अपनाने की एक तय प्रक्रिया का पालन किया गया है।

विवाद का मुख्य कारण हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया ने 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाया है, जो कि 15 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होगी।

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे वापस लेने की मांग की है। इसके जवाब में सरकार और भाजपा ने संसदीय समिति की अगस्त 2026 की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें यूपीआई इकोसिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए एक

लिखा कि एक तरफ पीएम मोदी ने एक बुजुर्ग मां को सम्मान और अपनापन दिया, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में उनका मजाक उड़ाया। यही फर्क है संस्कार और दिखावे की राजनीति में। जिस उम्र में सम्मान मिलना चाहिए, वहां राहुल गांधी का यह शर्मनाक रवैया उनकी सोच के बारे में क्या कहता है?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नैतिक दिवालियापन के सबसे निचले स्तर पर गिर गए हैं। छात्रों के साथ बातचीत का इस्तेमाल करके पीएम मोदी जी की दिवंगत मां का मजाक उड़ाना और उनका अपमान करना, बुनियादी मानवीय संवेदना और राजनीतिक संस्कृति की चौकाने वाली कमी को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस अब कॉमेडियन्स और जोकरों की पार्टी बनकर रह गई है। वे हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे जाएं और उस पर राहुल गांधी हंसें, यह दृश्य बेहद शर्मनाक और पीड़ादायक है। मां राजनीति का विषय नहीं होती।

गांव में पड़ोसियों की दबंगई व रास्ते के विवाद से परेशान

पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच

नितिन कुमार सिंह, बागपत। किरठल गांव में पड़ोसियों की कथित दबंगई और रास्ते के विवाद से परेशान एक परिवार ने अपने मकान के बाहर 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर लगाया मामला ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बन गया। मकान मालिक उदयवीर का आरोप है कि पड़ोसी रास्ते पर कब्जा किए हुए हैं और विरोध करने पर आए दिन गाली-गलौज कर परिवार को परेशान करते हैं। इससे परिवार को घर से आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उदयवीर का कहना है कि रास्ते के विवाद को लेकर पड़ोसियों से कई बार

चरणबद्ध राजस्व माडल को जल्द लागू करने की सिफारिश की गई थी। एमडीआर लागू करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था।

भाजपा का दावा है कि जब यह रिपोर्ट पास हुई, तब समिति में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी और गौरव गोगोई वहां मौजूद थे और उन्होंने कोई लिखित असहमति दर्ज नहीं कराई थी।

कहासुनी हो चुकी। मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन समाधान नहीं हो सका। तंग आकर परिवार ने मकान बेचने का निर्णय लिया और घर के बाहर 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर लगा दिया। घर में रहने के बावजूद उन्हें आने-जाने के रास्ते को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है।

पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर रास्ते से कथित कब्जा हटवाने और परिवार को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मकान पर लगा पोस्टर ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

केशरी दर्पण समाचार पत्र के ऑनलाइन पत्रकार बने।

www.kesharidarpan.com

पर रजिस्टर/लॉगिन करें।

KD सम्पादक सुभाष चंद
9837749557

फैक्ट्री लगाने के लिए 200 करोड़ रुपये का एमओयू साइन

नितिन कुमार सिंह, बागपत। औद्योगिक विकास के लिए अच्छी खबर है। उद्योग विभाग के साथ अब एक कंपनी ने फैक्ट्री लगाने के लिए 200 करोड़ रुपये का एमओयू साइन किया है। इस फैक्ट्री में बिजली के घरेलू उपकरणों का निर्माण होगा तथा 1500 युवाओं की रोजगार की राह आसान होगी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी 5.0 के लिए 55 निवेशकों कुल 3050 करोड़ के एमओयू कराए जा चुके हैं।

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत अक्टूबर या नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 होने की उम्मीद है। शासन ने बागपत को तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश कराने का लक्ष्य दिया हुआ है। अब उद्योग विभाग को बड़े निवेशक से निवेश कराने के लिए बड़ी सफलता मिली है। उपायुक्त उद्योग राजेंद्र कुमार ने बताया कि दिल्ली निवासी प्रवीण जैन ने बागपत के मवीकला में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के पास चार एकड़ भूमि पर फैक्ट्री लगाने के लिए विभाग के साथ दो दिन पहले 200 करोड़ रुपये का एमओयू साइन किया है। फैक्ट्री में आयरन प्रेस, पंखे तथा अन्य उपकरणों का निर्माण हुआ करेगा।

उद्यमी मित्र अर्पित सिंह ने बताया कि एमओयू करने पर निवेशक को जमीन की रजिस्ट्री कराने पर 75 प्रतिशत की स्टांप पर छूट मिलेगी, जिससे उनकी 1.50 करोड़ रुपये की बचत होगी। बताते चलें कि जीबीसी-5.0 के लिए 54 निवेशकों से 2850 करोड़ रुपये के एमओयू पहले साइन हो चुके हैं।

साक्षरता एवं संख्यात्मकता

मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन

नितिन कुमार सिंह, बागपत। रविवार को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए 293 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 5,093 निरक्षकों ने प्रतिभाग किया। निरक्षरों में अधिक महिलाएं शामिल रहीं।

खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों ने केंद्रों का निरीक्षण किया। शिक्षकों की कक्ष निरीक्षकों के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी। अंगूठा छाप के कलंक से मुक्ति पाने के लिए रविवार को निरक्षरों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए।

नोट: पत्र में छपे लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, सम्पादक का इनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। आप स्वयं जांच करें। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बागपत होगा।

RNI. No. UPHIN/2010/36806, मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुभाष चन्द ने इण्डियन प्रेस, राजेन्द्र नगर, मेरठ से छपवाकर कार्यालय ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट तहसील बडौत, जिला बागपत से प्रकाशित किया। सम्पादक: सुभाष चन्द, मो. 9837749557, प्रबन्धक सम्पादक: राजवीर सिंह, (किसी भी विवाद के लिए बागपत न्यायालय मान्य)